

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1538  
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का आंतरिक मूल्यांकन

†1538. श्री काली चरण सिंह:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन का कोई परिणाम-आधारित, तृतीय-पक्षीय या आंतरिक मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) अधिगम परिणामों, पहुँच, समानता, गुणवत्ता, शिक्षक क्षमता और संस्थागत प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कौन से संकेतक और मानदंड उपयोग किए गए हैं;
- (ग) ऐसे आकलन में पाई गई अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला-स्तरीय और अंतर-संस्थागत भिन्नताओं का ब्यौरा क्या है;
- (घ) निष्कर्षों की प्रतिक्रिया में आरंभ किए गए सुधारात्मक या पाठ्यक्रम-सुधार उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) एनईपी परिणामों की निरंतर निगरानी और आवधिक रिपोर्टिंग के लिए स्थापित संस्थागत तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शिक्षा मंत्रालय ने पहुँच, न्यास संगतमता, गुणवत्ता, अधिगम परिणाम और शिक्षक क्षमता से जुड़े अलग-अलग उपायों की निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन के लिए कई तंत्र बनाए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज+) 2024-25 के अनुसार, भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली में प्रमुख शैक्षिक संकेतकों में मापनीय सुधार पाया गया। इसमें लगभग

14.72 लाख स्कूलों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से बुनियादी से लेकर माध्यमिक स्तर तक के लगभग 24.7 करोड़ छात्रों के आंकड़े हैं। शिक्षकों की संख्या 98.07 लाख से बढ़कर 1.01 करोड़ हो गई, जिसमें कुल 54.82 लाख महिला शिक्षक हैं, जो अधिक लैंगिक-संतुलित कार्यबल को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में सभी स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ। अनुपात अब बुनियादी स्तर पर 10, प्रारंभिक स्तर पर 13, मध्य स्तर पर 17 और माध्यमिक स्तर पर 21 प्रदर्शित होता है। ये अनुपात 1:30 के एनईपी मानदंड से अधिक सुदृढ़ हैं, जो प्रत्येक छात्र पर सूक्ष्मता से ध्यान देने और बेहतर अधिगम परिणामों का समर्थन करते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 2023-24 की तुलना में प्रारंभिक परीक्षा (3.7% से 2.3%), मिडिल (5.2% से 3.5%), और माध्यमिक स्तर (10.9% से 8.2% तक) में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में उल्लेखनीय कमी पाई गई है। वर्ष 2024-25 में सभी स्तरों पर छात्र प्रतिधारण दर में सुधार हुआ। बुनियादी स्तर 98.0 प्रतिशत से बढ़कर 98.9 प्रतिशत हो गया। प्रारंभिक स्तर 85.4 प्रतिशत से बढ़कर 92.4 प्रतिशत हो गया। मिडिल स्तर 78.0 प्रतिशत से बढ़कर 82.8 प्रतिशत हो गया। माध्यमिक स्तर 45.6 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गया। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में मिडिल और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि दर्ज हुई। मध्य स्तर 89.5 प्रतिशत से बढ़कर 90.3 प्रतिशत पर पहुंच गया। माध्यमिक स्तर 66.5 प्रतिशत से बढ़कर 68.5 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि उच्चतर शिक्षा में बढ़ी हुई पहुंच और उच्च कक्षा में छात्रों की भागीदारी में वृद्धि को दर्शाती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे अधिगम परिणाम, पहुंच परिणाम, अवसंरचना, सुविधाएं, न्यायसंगत परिणाम आदि से 73 संकेतकों को मिलाकर प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, राज्य (पीजीआई) विकसित किया है। वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की पीजीआई-राज्य रिपोर्ट <https://pgi.udiseplus.gov.in/#/statepgi/home> पर देखी जा सकती है। इसी तरह, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, जिला एक जिला-स्तरीय मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग विकेंद्रीकृत तरीके से स्कूल शिक्षा परिणामों की तुलना करने और उनमें सुधार हेतु किया जाता है। इसमें परिणाम, कक्षा प्रक्रियाएं, अवसंरचना, सुरक्षा, डिजिटल शिक्षण और शासन शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक की पीजीआई-जिला रिपोर्ट <https://dpgi.udiseplus.gov.in/#aboutPgi> पर देखी जा सकती है।

"परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024" का आयोजन दिनांक 04.12.2024 को पूरे भारत में किया गया था, ताकि बुनियादी, प्रारंभिक और माध्यमिक चरणों (क्रमशः ग्रेड 3, 6 और 9) के अंत में छात्रों में दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझा जा सके। सर्वेक्षण में राष्ट्रव्यापी

781 जिलों के 74,229 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक छात्रों और 2.70 लाख शिक्षकों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड <https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en> पर उपलब्ध हैं।

उच्चतर शिक्षा में, एक वार्षिक वेब आधारित 'अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)' उच्चतर शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण डेटा स्रोत है। एआईएसएचई 2022-23 (अंतिम) रिपोर्ट में एआईएसएचई 2014-15 की तुलना में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों और कॉलेजों की संख्या क्रमशः 760 से बढ़कर 1213 और 38498 से बढ़कर 46624 हो गई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन वर्ष 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है, जिसमें महिला नामांकन 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हो गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 46.07 लाख की तुलना में वर्ष 2022-23 में 69.13 लाख हो गया। अनुसूचित जनजाति छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 28.72 लाख हो गया है। कुल एसटीईएम नामांकन 99.76 लाख है। संकाय की संख्या वर्ष 2014-15 में 14.73 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 16.64 लाख हो गई है, जिसमें महिला संकाय की संख्या 5.7 लाख से बढ़कर 7.36 लाख हो गई है। कुल जीईआर वर्ष 2014-15 में 23.7 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 29.5 हो गया।

वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, क्यूएस रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं शामिल हैं, जबकि 2015 में यह संख्या 11 थी। वर्ष 2025 के लिए क्यूएस विषय रैंकिंग में 79 भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं शामिल थे, जो पिछले वर्ष के 69 से 10 की वृद्धि है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 के अनुसार, 294 भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं की विशेषताएं हैं।

एनईपी के तहत अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिए जाने से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई ) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2020 में 48 से बढ़कर वर्ष 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है।

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा क्षेत्र में समग्र गुणवत्ता और विकास में व्यापक और प्रगतिशील सुधार सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करती हैं। एनईपी 2020 के लिए नीति को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक आयोजना, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।

\*\*\*\*\*